(ग) यदि हां, तो क्या सरकार नई कृषि और नागरिक उपभोक्ता आपूर्ति नीति बनाने का विचार रखती है; और

(घ) उक्त नीति कब तक तैयार हो जाएगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) से घ) कृषि नीति में अधिक पैदावार देने वाली किस्मों, सिंचाई का विस्तार तथा आधुनिक आदानों का उपयोग पर आधारित वृद्धि जिसमें महत्वपूर्ण जिंसों के मामले में उत्पादक को न्यूनतम समर्थन मूल्य का आश्वासन दिया गया है, पर अब तक मुख्य बल दिया जाता रहा है। कृषि के सतत विकास को बढ़ावा देने तथा आर्थिक उदारीकरण और विज्ञान व प्रौद्योगिकी में प्रगति के परिणामस्वरूप विकसित नये अवसरों का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए कृषि संबंधी एक विस्तृत राष्ट्रीय नीति निरूपण के अन्तिम चरणों में है। खुले बाजार मूल्यों को उदार बनाने के लिये सरकार की नीति के एक साधन के रूप में तथा कुछ आवश्यक जिंसों की उपलब्धता आसानी से प्रदान किये जाने वाले मूल्यों पर सुनिश्चित करके सातवें दशक के मध्य में एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत में शुरू की गई थी। वर्षों के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी को सेवा प्रदान करने में असफलता, इसका शहरी पक्षपात, उन राज्यों में नगण्य कवरेज जहां ग्रामीण निर्धन का आबादी घनत्व सबसे अधिक है, तथा आपूर्ति के लिये पारदर्शी तथा जिम्मेदार व्यवस्था के अभाव से सम्बन्धित मामलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अत्यधिक आलोचना हुई है। इसे महसूस करते हुए सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की है जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली आबादी के लिये प्रत्येक अभिज्ञात परिवार को प्रतिमाह प्रति परिवार 10 किग्रा० खाद्यान्न की दर पर विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न प्रदान किया जाता है।

Food and Agro-Industries Management Policy

312. SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA:
SHRI KAPIL SIBAL:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a sub-committee constituted under convenership of Nusli Wadia has submitted a report on food and agro-industries management policy;

(b) if so, the date on which the said report was received by the Government togetherwith the details of suggestions made in this report;

(c) whether a final decision has been taken by Government to implement these suggestions; and

(d) if so, the details thereof; and if no, decision has been taken, the reasons for delay in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) to (d) A sub-group in the nature of a Task Force on Food and Agro-Industries Management Policy was constituted by the Prime Minister's Office (PMO), in pursuance of the proceedings of the first meeting of the Prime Minister's Council on Trade and Industry held in September, 1998. The Task Force submitted its report on 14th December, 1998. The major suggestions made by the Task Force relate to increasing food production, utilizing and marketing the food produced and creating an enabling environment for promoting food and agro-industries through realignment of tax framework, restructuring administrative framework and promoting safety and quality of food and focus on exports. These suggestions have been remitted to the Ministries concerned for initiating appropriate action on the issues relating to them.

गो-हत्या पर प्रतिबंध

313. **चौधरी हरमोहन सिंह यादाव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का गो-हत्या पर प्रतिबंध लगाने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान गो-मांस के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?